Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

दृष्टि The Vision

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

इतिहास

वैकल्पिक विषय

द्वारा- अखिल मूर्ति

कक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- कक्षा में ही संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी "नवीन परिवर्तनों" के अनुरूप।
- उत्तर लेखन अभ्यास एवं मानचित्र के अध्ययन पर विशेष बल।
- विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा एवं उनके आदर्श उत्तर प्रारूप का निर्माण।
- नियमित जाँच परीक्षा।

641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501, 011-47532596

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

द जिस्ट

उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

योजना

- हस्तशिल्प का स्थायित्व
- वस्त्र कामगारों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ
- वस्त्र क्षेत्र में रोज़गार सृजन और समावेशी विकास
- वस्त्र एवं परिधान निर्यात: उभरते बाज़ार
- तकनीकी वस्त्र : एक उदीयमान उद्योग
- भारत में वस्त्र उद्योग : स्थानीयकरण
- समय के साथ बदलता भारतीय हैंडीक्राफ्ट

कुरुक्षेत्र

- स्वच्छ भारत मिशन : व्यवहार परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन तक
- मन बनाओ, शौचालय बनाओ-ग्रामीण गुजरात का नया मंत्र
- ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का आकलन
- नदियों की स्वच्छता की चुनौती
- स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन

डाउन टू अर्थ

- ज़ीरो नेट में ही भविष्य है
- भारत में NZE इमारतें
- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कमी लाने के लिये संधि
- कस्तूरी मृग की मंद पड़ती खुशबू
- कृषि जलाशय
- रहस्यमयी बुखार
- एक वहनीय संहिता का विचार

इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली

- जल विवाद
- सरकार के लक्ष्य
- बौद्धिक संपदा
- जनजातीय कुपोषण
- नागरिक-सैन्य संबंध
- एफसीएनआर-बी जमाराशियाँ

द इकॉनमिस्ट

- पांडाओं की बढ़ती संख्या
- असहमति से सहमति की ओर (G-20 तथा वर्ल्ड इकोनॉमी)
- खुले दरवाज़े किन्तु भिन्न-भिन्न कानून (खाड़ी प्रवासन के संबंध में)
- क्षेत्रीय विकास
- परमाणु ऊर्जा-एक प्रज्वलित भविष्य
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
- विकास और वैश्वीकरण

साइंस रिपोर्टर

- कार्बन के भार को कम करना
- बाँस : हरा सोना

द हिन्दू

- कम प्रदूषण वाले मार्ग का अनुकरण
- ओपेक की महत्ता
- साधनों व साध्यों के बारे में
- बीटी कपास के मुद्दे पर जंग
- जापान के साथ भारत का नाभिकीय समझौता
- कावेरी जल विवाद
- पूर्वाग्रह को समाप्त करना
- सिंगूर फैसले की विशेषता
- शुद्ध विनिमय की रणनीति का अनुपालन
- विभाजित राष्ट्रों का नेतृत्व
- कैरोसिन मुक्त भारत की ओर एक कदम
- शीतयुद्ध के तनाव की ओर पुन: वापसी
- पुराने संबंधों को फिर से गढ़ना
- ब्रिक्स देशों के मज़बूत होते संबंध
- अनिश्चितता से घिरा चीन
- शहरों को समावेशी बनाना

तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com
Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

योजना

योजना पत्रिका के अक्तूबर 2016 अंक (वस्त्र उद्योग: नया ताना-बाना) का सार

हस्तशिल्प का स्थायित्व – स्मृति जुबिन ईरानी

- भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक असंगठित, विकेंद्रीकृत तथा श्रम गहन कुटीर उद्योग है जो ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में न केवल लोगों को रोज़गार प्रदान करता है बल्कि देश के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है।
- भारतीय हस्तशिल्प से निर्मित सामान को अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्राँस, लैटिन अमेरिकी देशों, इटली, नीदरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों को निर्यात किया जाता है।
- वस्तुत: भारतीय हस्तशिल्प भारत के औद्योगिक क्षेत्र की ताकत है क्योंकि इसकी मुख्य आधारभूत आवश्यकताएँ, जैसे– प्रचुर मात्रा में मिलने वाला सस्ता श्रम, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, कम पूंजी निवेश और अद्वितीय शिल्प कौशल इसे वैश्विक स्तर न केवल प्रशंसा का पात्र बनाती हैं अपितु देश की निर्यात क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि का कारक बनती हैं। इन सबके बावजूद इस क्षेत्र को साक्षरता और शिक्षा के निम्न स्तर, आधुनिक तकनीकी कौशल के अभाव, कच्चे माल में अपर्याप्त निवेश और कमज़ोर संस्थागत ढाँचे जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- हस्तशिल्प की उत्पादन प्रक्रियाओं में कार्बन का कम इस्तेमाल होता है, और जहाँ तक संभव होता है, इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के साथ ही प्राकृतिक और जैविक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। हस्तशिल्प उत्पादन अपेक्षाकृत कम कुशल, गृह आधारित महिलाओं को आय और रोज़गार का एक ज़रिया प्रदान करता है, जिससे घर और समुदाय के भीतर उनकी स्थिति में सुधार होता है।
- इस क्षेत्र की क्षमता के दोहन के लिये भिन्न प्रकार से निवेश किये जाने की ज़रूरत है ताकि पारंपरिक शिल्प का संरक्षण किया जा सके, इस क्षेत्र को मज़बूती मिले और कारीगरों की आय में सुधार हो। इसके लिये कारीगरों को एक मूल्य-शृंखला में समायोजित किया जाना चाहिये।
- कपड़ा मंत्रालय के तहत आने वाले हथकरघा उपायुक्त ऑफिस के वीवर्स सर्विस सेंटर्स हथकरघा बुनकरों के कौशल उन्नयन, क्षमता-निर्माण और तकनीकी हस्तक्षेप में निर्णायक भूमिका निभाते हैं जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो। केन्द्र बुनकरों को डिज़ाइन इनपुट प्रदान करते हैं तथा उनके लिये बुनाई के दौरान, उससे पूर्व और उसके उपरांत विभिन्न विषयों, जैसे- बाइंडिंग, रैपिंग, साइज़िंग, डाइंग, डॉबी जैकार्ड नुमैटिक वीविंग, डिज़ाइन मेकिंग (सीएडी) इत्यादि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं।
- 'मेगा हथकरघा क्लस्टर' योजना भी विशिष्ट उत्पादों के लिये भौगोलिक स्थानों को चिह्नित करने, डिज़ाइन इनपुट प्रदान करने तथा बुनियादी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने का कार्य कर रही है जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार की बदलती मांगों को पूरा किया जा सके और हथकरघा उद्योग के लाखों बुनकरों का जीवन स्तर सुधारा जा सके।
- इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल विकास एवं हथकरघा उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। समझौते के अनुसार, दोनों मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से ज्ञान साझा करने, संसाधनों को अनुकूल बनाने और संस्थाओं के बीच तालमेल के माध्यम से हथकरघा बुनकरों के लिये कौशल विकास और उद्यमिता विकास जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने हेतु प्रतिबद्धता जताई है।
- 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिहाज़ से एक महत्त्वपूर्ण पहल है। गत वर्ष 7 अगस्त को इसे पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत मिलने वाले उत्पादों के कच्चे माल, अलंकरण, वीविंग, डिज़ाइन और दूसरे गुणवत्ता मानक उच्च स्तर के हैं जिनके उत्पादन में सामाजिक एवं पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन किया जाता है।
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) ने अपने पाठ्यक्रम में क्राफ्ट क्लस्टर इनीशिएटिव को एकीकृत किया है जिससे विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बुनकरों के साथ काम करने का मौका मिलता है। इससे न केवल विद्यार्थियों को इस क्षेत्र की चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है बल्कि बुनकरों और कारीगरों के लिये भी आधुनिक बाज़ार की चुनौतियों को समझना एवं उसके अनुसार स्वयं को ढालना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, चेन्नई स्थित निफ्ट केरल के कोझिकोड क्लस्टर (वडाकरा, कोयलांदी और कोझिकोड) के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह क्लस्टर दो दशक पुराने शिल्प-हथकरघा बुनाई तथा 'उरु' के लिये प्रसिद्ध है।
- पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धी और प्रभावी ढंग से हथकरघा उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिये अनेक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार किये जा रहे हैं। ऐसे बाज़ारों का निर्माण करके कारीगरों को आजीविका अर्जन के लिये सशक्त किया जा सकता है। पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम का असम आधारित संगठन 'एक्वा वीव्स', प्रदूषित पानी में होने वाले बारहमासी फूल हायसिन से बैग, घर की साज-सज्जा का सामान और यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाता है।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र पत्रिका के अक्तूबर 2016 अंक (ग्रामीण स्वच्छता-बदलती मानसिकता: मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना) का सार

स्वच्छ भारत मिशन : व्यवहार परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन तक – नरेंद्र सिंह तोमर

- सम्पूर्ण स्वच्छता कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर ज़ोर देने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का सूत्रपात किया था।
- एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) की परिकल्पना मात्र शौचालयों के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में की गई है। साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के अलावा यह मिशन क्षमता निर्माण, समन्वय, प्रचालन तंत्र एवं वित्त आदि के संदर्भ में प्रगति को अवरुद्ध करने वाली रुकावटें मिटाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- एसबीएम-जी ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ), साफ-सुथरा एवं स्वच्छ बनाते हुए स्वच्छता के स्तर में सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- स्वच्छ भारत, स्वच्छता की दिशा में उठाए गए पूर्व कदमों से अलग है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा सृजित अवसरों के अनुसार कॉरपोरेट सोशल उत्तरदायित्व (सीएसआर) का लाभ उठाते हुए कॉरपोरेट क्षेत्र की अति सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मिशन के साथ जुड़ते हुए देश की कई नामी कंपनियों को भी 'स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत' में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित किया है।
- 20 ज़िलों और 80 हज़ार से भी ज़्यादा गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने के साथ खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है। गंगा के किनारे बसे 1523 गाँव ओडीएफ बन चुके हैं। वर्तमान समय तक लगभग 23.5 मिलियन से ज़्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छता पखवाड़ा' आरंभ किया है जिसमें सभी मंत्रालयों ने अपने संबंधित तथा अधीनस्थ कार्यालयों व अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थलों को साफ-सुथरा करने के लिये एक निर्धारित समय-सारणी का पालन करना सुनिश्चित किया है।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने अपने विकास भागीदारों के साथ 'ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस' का आयोजन इस कार्य में धर्मगुरुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिये किया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद को सुरक्षित शौचालयों तथा जल की उपलब्धता पर अधिकतम प्राथमिकता देने के साथ चार विभिन्न मानकों पर प्रत्येक ज़िले की स्वच्छता का निर्धारण करने की ज़िम्मेदारी भी दी गई।

मन बनाओ, शौचालय बनाओ- ग्रामीण गुजरात का नया मंत्र – डॉ. जयंती एस. रवि

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि 60 प्रतिशत से ज़्यादा ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है, स्वच्छ भारत मिशन को दो उपमिशनों- ग्रामीण भारत के लिये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और शहरी भारत के लिये स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में विभाजित किया गया है।
- एसबीएम केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक देशव्यापी कार्यक्रम है, जिसका सभी राज्यों की सरकारों ने यथोचित स्वागत और समर्थन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसने राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण तैयार किया है, जिससे उनके बीच बौद्धिकता को महत्त्व देने वाली संस्कृति

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

डाउन टू अर्थ

डाउन टू अर्थ पत्रिका के 1-15 अक्तूबर, 2016 अंक में प्रकाशित कुछ महत्त्वपूर्ण लेखों का सार

ज़ीरो नेट में ही भविष्य है

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान रखने वाली लगभग 40% वस्तुओं का उपभोग विनिर्माण उद्योग में किया जाता है। इसके साथ ही इस उद्योग से 40–50% ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है, जिससे विश्वभर में धारणीय इमारतों व शहरों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में पता चलता है।
- किसी इमारत की धारणीयता की गणना, उसकी ऊर्जा कुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता तथा ऊर्जा उपभोग को कम करने में सहायक इसकी वास्तुशिल्पीय रूपरेखा व विनिर्माण के आधार पर की जा सकती है।
- किसी इमारत के कुल ऊर्जा उपभोग में शीशा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि किसी शीशे के ऊष्मीय व प्रकाश सम्प्रेषण (transmittance) गुण भिन्न-भिन्न तरीके से परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार, इमारत प्रतिरूप कार्यक्रम (building simulation programme) के द्वारा दिन के प्रकाश व इमारत की ऊष्मा अवशोषण क्षमता के बीच एक संतुलन बनाया जा सकता है, जिससे ऊष्मीय व दृश्यात्मक विशेषताओं वाले अनुकूलतम शीशे का एक क्षेत्र निर्मित किया जा सके।
- धारणीय इमारतों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये नियरली ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग (NZEBs) तथा जल या कार्बन इमारतों की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया है। NZEBs (Nearly Zero Energy Building) नवीकरणीय ऊर्जा से युक्त एक ऐसी इमारती व्यवस्था है जो कि संबंधित इमारत की सालभर की ऊर्जा आवश्यकता के हिसाब से ऊर्जा उत्पादित करती है।
- हालाँकि, ऊर्जा कुशल व नेट ज़ीरो एनर्जी (NZE) इमारतों से संबंधित बहुत से समाधान इस तरह से उत्पाद-आधारित होते हैं जिनसे किसी परियोजना की समस्त समस्याओं का एक समेकित व व्यापक समाधान प्राप्त होने की बजाय अलग-अलग बिन्दुओं का हल खोजा जाता है। फलस्वरूप, हरित इमारतों के विनिर्माण में निवेश करने से असफलता ही हाथ लगती है।

भारत में NZE इमारतें

- भारत में वास्तविक रूप से धारणीय व हरित भवनों का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती है। डिज़ाइन एवं डेवलपर्स उद्योग की तरफ से लापरवाही की भी एक बड़ी समस्या है। वस्तुत: ये लोग पश्चिमी व भारतीय जलवायु के बीच मौजूद भिन्नताओं पर ध्यान दिये बगैर पश्चिमी देशों की डिज़ाइनों व आरामदायक नमूनों की नकल करते हैं।

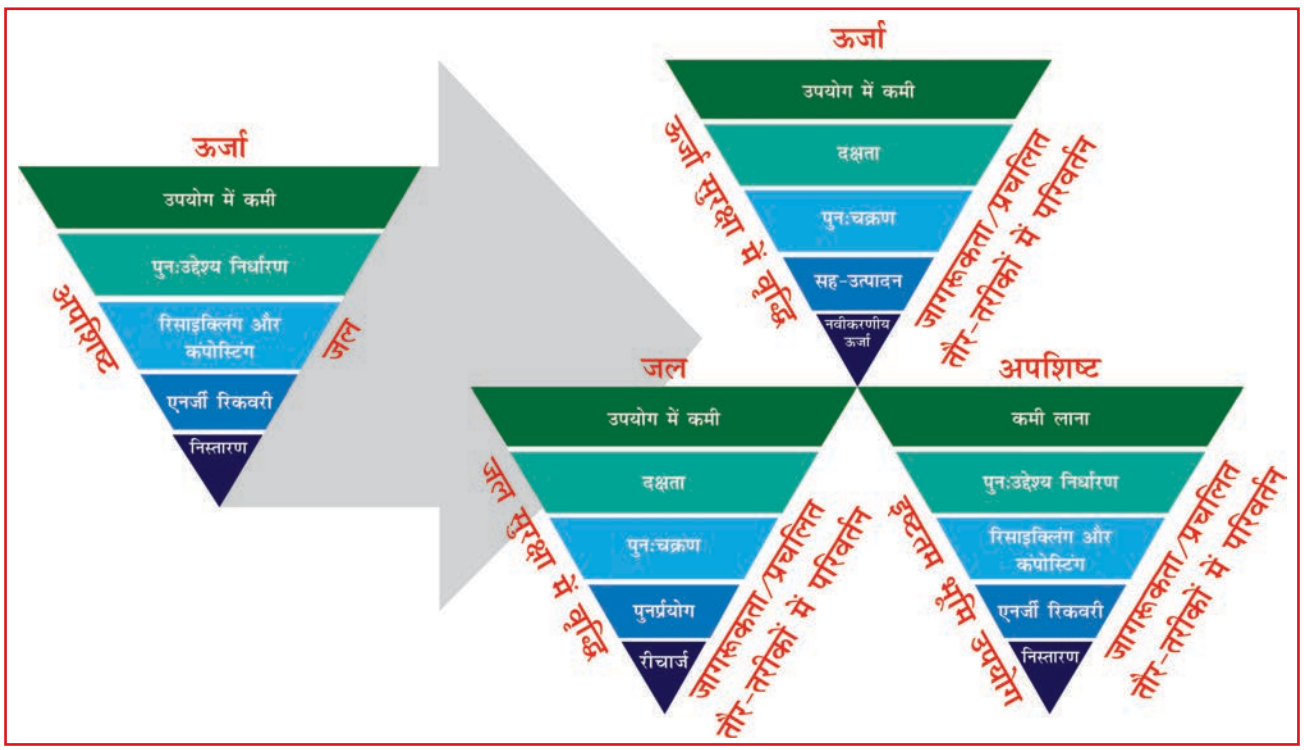

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली

इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली पत्रिका के 17 एवं 24 सितंबर, 2016 के अंकों में प्रकाशित महत्त्वपूर्ण लेखों का सार

जल विवाद

कावेरी जल विवाद के विभिन्न आयाम: विश्वसनीय संस्थानों की ज़रूरत

- ईपीडब्ल्यू के एक संपादकीय में लिखा गया है कि कावेरी जल विवाद काफी पुराना है तथा इस पर मद्रास प्रांत व मैसूर रियासत के बीच वर्ष 1892 में और उसके बाद वर्ष 1924 में समझौता भी हो चुका है। फिर 1990 के दशक तक कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (CWDT) स्थापित हो चुका था, और तब तक इन क्षेत्रों की जनसंख्या काफी बढ़ चुकी थी और मद्रास प्रांत तमिलनाडु हो गया था, जबकि मैसूर कर्नाटक राज्य बन चुका था। कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने चार तटीय राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुच्चेरी) के बीच कावेरी जल के बँटवारे संबंधी अपने वर्ष 2007 के अंतिम निर्णय तक पहुँचने में 17 वर्षों का लंबा समय लिया।
- इसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद वर्ष 2013 में अधिसूचित करने में अगले 6 साल लगाए और जब अधिसूचना जारी हुई तो सभी राज्य इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। फलस्वरूप, साझा जल के आवंटन का कार्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है।
- कर्नाटक का हमेशा से यह मानना है कि उसे कभी भी इसका उचित हिस्सा नहीं मिला, जबकि एक उच्च तटीय राज्य होने के कारण इसके पास नदी का बहाव नियंत्रित करने की अधिक शक्ति है। साथ ही, नदी का स्रोत कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, अत: इसकी विशिष्ट स्थिति होने के कारण अगर वह नदी पर बांध बना ले (जैसा कि वह पहले भी कर चुका है) तो वह वास्तव में जल के बहाव को नियंत्रित कर सकता है। फिर भी, एक सुविदित तथ्य यह भी है कि कावेरी बेसिन में कर्नाटक के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता तमिलनाडु के जलाशय की अपेक्षा कम है।
- बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण, भू-जल स्रोतों, परम्परागत तालाबों व जलाशयों की उपेक्षा व अति दोहन के फलस्वरूप सरकार शहरी मांग को संतुष्ट करने के लिये सतह के जल स्रोतों, जैसे कि नदियों से जल प्राप्त करने को बाध्य हुई है। जल सघन फसलें अब उन्हीं ज़िलों में की जाती हैं जहाँ कावेरी का जल उपलब्ध है।
- वर्ष के ऐसे महीनों में, जब जलाशयों का जल-स्तर कम हो जाता है तो जल की मांग व पूर्ति के बीच का संबंध और ज़्यादा बिगड़ जाता है, फलस्वरूप, जल के बँटवारे का सबसे आदर्श नुस्खा भी दोनों पक्षों को परेशानी में डाल देता है। कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच विवाद में हूबहू यही स्थिति निकलकर सामने आई। CWDT ने बँटवारे की एक ऐसी तरकीब निश्चित की है जो कि 'सामान्य' वर्षा वाले वर्षों के लिये कारगर है, लेकिन यह उन तनावग्रस्त स्थिति वाले वर्षों के लिये असफल है जो कि तीन या चार वर्ष में एक बार आते हैं। जहाँ वर्षा की मात्रा में कोई खास नाटकीय बदलाव नहीं होता है, वहाँ भी मौसम प्रारूपों में बदलाव व मानसून की अस्थिर प्रकृति के कारण यह स्थिति महीनों तक व्याप्त रहती है और इससे जलाशयों में भंडारित जल की मात्रा प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर, इस वर्ष कर्नाटक व तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में स्थित जलाशयों का भंडारण पिछले 10 वर्षों की औसत वर्षा से क्रमश: 30% व 49% कम था।
- जल-आवंटन समझौते को क्रियान्वित करने के लिये विश्वसनीय संस्थानों की स्थापना करने की आवश्यकता है। कावेरी नदी प्राधिकरण व कावेरी निगरानी समिति, कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल की सुनवाई के दौरान मौजूद अंतरिम निकाय थे, किन्तु कावेरी प्रबन्धन बोर्ड द्वारा अभी वे प्रतिस्थापित नहीं किये गए हैं। केंद्र सरकार को यह कदम शीघ्र उठाना चाहिये ताकि जल बँटवारे के पूरे विमर्श से राजनीति को हटाया जा सके तथा इसे वर्षण, भंडारण स्तर व संरक्षण जैसे उचित तर्कों पर केन्द्रित किया जा सके।

सरकार के लक्ष्य

कल्याणकारी योजनाएँ : "लक्षित करने" की समस्या

- एक संपादकीय लेख में टिप्पणी की गई है कि सरकार संख्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अति उत्साह में कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावोत्पादकता को जोखिम में डाल रही है।
- आपातकाल (1975–76) के दौरान का एक उदाहरण काफी महत्त्वपूर्ण है जब संजय गांधी ने बंध्याकरण कार्यक्रम को बलपूर्वक लागू करवाया था। नसबंदी नामक इस कार्यक्रम के कारण सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गलत छवि प्रस्तुत हुई।
- वर्ष 1994 में सरकार ने 'जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' में अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बाद परिवार कल्याण उपक्रमों में लक्ष्य तय करने की अवधारणा का त्याग कर दिया।
- इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 6 राज्यों के 25 गाँवों व 4 शहरों के 52 जीवित व्यक्तियों के साक्षात्कारों व सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त सूचनाओं पर आधारित एक विवरणात्मक छानबीन की गई, जिसके निष्कर्ष नीति-निर्माताओं को चिंता में डालने वाले रहे। 15 अगस्त, 2014 को बहुत धूमधाम से वित्तीय समावेश योजना (जन-धन योजना) की घोषणा किये जाने के बाद बैंक अधिकारियों ने अति उत्साहित होकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 1 रुपए की धनराशि गैर-कानूनी तरीके से ज़ीरो बैलेंस खातों में (इसकी परिभाषा बदलने के लिये) डाल दी।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

द इकॉनमिस्ट

द इकॉनमिस्ट पत्रिका के 3, 10 एवं 24 सितंबर, 2016 के अंकों में प्रकाशित महत्त्वपूर्ण लेखों का सार

पांडाओं की बढ़ती संख्या

- 5 सितंबर, 2016 को 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर' नामक एक पर्यावरणीय समूह (विभिन्न देशों की सरकारों एवं एनजीओ से संबंधित) ने पांडा (अंतर्राष्ट्रीय मनोहरता का प्रतीक) 'संकटग्रस्त' (Endangered) श्रेणी से हटाकर 'अतिसंवेदनशील' (Vulnerable) श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है।
- चीन में विगत तीस सालों के दौरान पांडाओं में प्रजनन को बढ़ावा देने के लिये बहुत से प्रयास किये गए हैं। हालिया सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, पांडाओं की संख्या में वर्ष 1988 के 1114 की अपेक्षा वर्ष 2013 में 1864 तक की वृद्धि दर्ज़ की गई है। जंगली क्षेत्र (दक्षिणी-पश्चिमी चीन के घने बाँस के जंगलों) में हुई पांडाओं की वृद्धि पांडाओं के निवास स्थान में हुए सुधार को दर्शाती है।
- वर्तमान में चीन में पाए जाने वाले दो प्रकार के पांडाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज़ की जा रही हैं। इनमें पहला है, जंगली पांड़ा (संकटग्रस्त) तथा दूसरा है पालतू पांडा (Captive Panda)। हालाँकि, पालतू पांडा संख्या में काफी कम हैं तथापि इनकी प्रजनन क्षमता काफी अधिक होती है।
- जंगली पांडाओं की जनसख्या में वर्ष 2003 से वर्ष 2013 के मध्य मात्र 268 यानी केवल 17% की वृद्धि दर्ज़ की गई है, जबकि इतने ही समय में पालतू पांडाओं की संख्या 164 से बढ़कर 375 हो गई है यानी लगभग दोगुनी।
- पांडा प्रजाति की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इनकी प्रजनन क्षमता अत्यधिक निम्न होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मादा पांडा 1 वर्ष में केवल कुछ ही दिनों के लिये गर्भधारण क्षमता अर्जित कर पाती है, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या में बहुत निम्नगति से वृद्धि होती है।
- हालाँकि पालतू पांडाओं के प्रजनन में भी काफी दिक्कतें आती हैं। पालतू होने के कारण एक लंबे समय तक लोग इनकी प्रजनन प्रक्रिया की प्राय: उपेक्षा करते रहे हैं; परंतु बदलते समय के साथ-साथ जैसे-जैसे पांडाओ के शरीर, क्रियाओं, गतिविधियों इत्यादि के विषय में शोध किया गया, फलस्वरूप इनके संबंध में मनुष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में भी व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। फलस्वरूप वर्तमान में इनकी संख्या में वृद्धि में हो रही है तथा इनका अस्तित्व सुरक्षित है।

असहमति से सहमति की ओर (G-20 तथा वर्ल्ड इकोनॉमी)

- G-20 समूह का 11वाँ शिखर सम्मेलन पूर्वी चीन के हांग्झाऊ शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि अमेरिका और चीन द्वारा पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते की पुष्टि कर दी गई है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा उल्लिखित आँकड़ों के अनुसार, 2016 पाँचवा वर्ष होगा जब वैश्विक वृद्धि दर पिछले पाँच वर्षों से लगातार 3.7% से कम के स्तर पर रहेगी। गौरतलब है कि 3.7% वैश्विक आर्थिक मंदी के पूर्व के दो दशकों की वृद्धि दर की औसत अनुमानित दर है।
- वस्तुत: G-20 समूह स्वयं द्वारा वर्ष 2014 में तय किये गए लक्ष्य से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा हैं। हालाँकि G-20 की सफलता-असफलता को केवल इसकी आर्थिक वृद्धि दर से मापना अप्रासंगिक होगा, वह भी तब जब समूह के बड़े सदस्य अपने उत्तरदायित्वों से पीछे हट रहे हैं।
- G-20 के विस्तार के संबंध में एक सकारात्मक पक्ष यह है कि भले ही यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाली संभावित समस्याओं का समाधान निकाल पाने में सफल न हो पा रहा हो किन्तु उनका सामना करने का पुरज़ोर प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि G-20 समूह फौरी तौर पर एक बेडौल संगठन प्रतीत होता है परन्तु

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

साइंस रिपोर्टर

साइंस रिपोर्टर पत्रिका के अक्तूबर 2016 अंक में प्रकाशित कुछ महत्त्वपूर्ण लेखों का सार

कार्बन के भार को कम करना

- पेरिस समझौता ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने, अनुकूलन करने तथा वर्ष 2020 में शुरू होने वाली वित्तीय पहलों से संबंधित है।
- वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के संकेन्द्रण को स्थिर करके जलवायु नियंत्रण के लिये वास्तविक चुनौती ईमानदार कदम उठाने की है।
- ग्रीनहाउस गैसों के अनर्थकारी प्रभाव अब अधिक स्पष्ट रूप में सामने आ रहे हैं, जैसे- उग्र मौसमी घटनाएँ, बार-बार आने वाली आपदाएँ, सूखे व बाढ़ की आवृत्ति में बढ़ोत्तरी, फसल उत्पादकता में कमी, जल का अभाव व रोगवाहक-जन्य बीमारियाँ।

कार्बन अधिग्रहण (Carbon Sequestration)

इसकी उत्पत्ति 'वैश्विक कार्बन चक्र' के अंतर्गत होती है। वायुमंडल के साथ-साथ जलमंडल, जैवमंडल व बर्फमंडल (धरती का जमा हुआ भाग) में कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूपों में निरंतर होने वाले रूपांतरणों के माध्यम से चलने वाले कार्बन चक्र के द्वारा पार्थिव तंत्र में कार्बन संतुलन को व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के कुछ रूपांतरण निम्नलिखित हैं:

- कार्बन डाइऑक्साइड जल में विघटित होकर HCO_3 में परिवर्तित हो जाती है।
- यह खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है।
- पौधे दिन के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इसे कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, यह प्रक्रिया प्रकाश-संश्लेषण कहलाती है।
- सूक्ष्म शैवाल समुद्री जल व अपशिष्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा बायोमास का उत्पादन करते हैं।
- अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हुए बैक्टीरिया व आद्य जीवाणु (Archaea) कार्बन डाइऑक्साइड को जैव पदार्थ में रूपांतरित कर देते हैं।
- समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और फाइटोप्लैंकटन की वृद्धि में योगदान देता है।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

द हिन्दू

'द हिन्दू' समाचार पत्र में अक्तूबर 2016 में प्रकाशित कुछ महत्त्वपूर्ण लेखों का सार

कम प्रदूषण वाले मार्ग का अनुकरण (1 अक्तूबर)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुमानित आँकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 6,00,000 लोगों की हवा में मौजूद प्रदूषण के महीन कणों के कारण मृत्यु हो जाती है।
- डब्ल्यूएचओ 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज' नाम से एक अध्ययन करा रहा है जिसके तहत प्रदूषण से होने वाली विभिन्न बीमारियों जैसे- हृदयघात, खुजली, शरीर में चकते पड़ जाना, सदमा लगना, साँस लेने में तकलीफ होना इत्यादि को चिह्नित किया जाएगा।
- भारत में मौजूद प्रदूषणकारी सूक्ष्म कणों पर आधारित आँकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रदूषण फैलाने वाले इन कणों का उद्गम वस्तुतः बायोमॉस आधारित पदार्थों अर्थात् ईंधन हेतु लकड़ियों, गोबर के उपलों, कोयले तथा धान की भूसी को जलाने से होता है।
- अधिक विकसित स्थानों जैसे शहरों में इन महीन कणों की मौजूदगी का मुख्य कारण भवन निर्माण के दौरान फैलने वाला कचरा, सड़क से उड़ने वाली धूल तथा दिन-प्रतिदिन बढ़ते वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला धुआँ है।
- शहरी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में अपेक्षित पहलू निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की प्रत्यक्ष अवहेलना करना रहा है। इन नियमों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले निर्माण पदार्थों का सतत् निपटारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- इन नियमों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि नगरपालिका तथा सरकारी ठेकेदारों को निर्माण तथा तोड़-फोड़ से उत्पन्न कचरे का तकरीबन 20% प्रयोग करना होगा तथा स्थानीय प्रशासन को भी कचरे के स्वस्थ निपटान हेतु जगह-जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था करनी होगी।
- स्वच्छ ईंधन तथा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित चूल्हों के प्रयोग द्वारा देश के उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों में प्रदूषण के सूक्ष्म कणों (Particulate Matter) को कम करने में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकेगी।
- शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिये एक योजना बनाई जानी चाहिये, जिसके तहत खाली पड़े स्थानों में पौधों को रोपने तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करने के लिये इसमें स्थानीय लोगों को शामिल किये जाने का प्रावधान निहित हो। इन सभी प्रयासों के बलबूते ही PM_{10} तथा $PM_{2.5}$ के स्तर को कम किया जा सकता है।

ओपेक की महत्ता (3 अक्तूबर)

- हाल ही में अल्जीयर्स (अल्जीरिया की राजधानी) में हुई ओपेक देशों की बैठक में एक अहम समझौते पर अंतिम मोहर लगा दी गई। इसके तहत वैश्विक तेल बाज़ार में मांग एवं संतुलन को नियंत्रित करने के प्रयासों के मद्देनज़र तेल उत्पादक संघों के सामूहिक उत्पादन को घटाकर 7,00,000 बैरल प्रतिदिन करने का अहम फैसला लिया गया है।
- यह पूर्व निर्धारित था कि वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ार में पिछले दो वर्षों से आ रही गिरावट को रोकने के लिये ओपेक समूह को कोई निर्णायक कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। हालाँकि अभी तक यह अस्पष्ट है कि क्या इन सभी सदस्य देशों के बीच उत्पादन में कमी को लेकर अर्थपूर्ण सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, क्योंकि ओपेक देशों के समूह में छोटा एवं अल्पविकसित पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र गैबन, संकटग्रस्त वेनेजुएला तथा ईरान और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देश भी शामिल हैं।
- पिछले आठ सालों में पहली बार तेल के उत्पादन में की गई कटौती को समूह के सबसे बड़े तेल उत्पादक राष्ट्र सऊदी अरब के द्वारा यह कहकर मौन स्वीकृति प्रदान की गई कि सऊदी अरब के "pump-at-will" दृष्टिकोण ने इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया है। हालाँकि, यह पॉलिसी उत्तरी अमेरिका के तेल उत्पादकों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से लाई गई थी। वस्तुतः इसमें अमेरिका के शैल गैस संबंधी हितों को भी निशाना बनाया गया; परन्तु बावजूद इसके, इस रणनीति के तहत सबसे अधिक नुकसान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को ही पहुँचा है।
- इस सबके विपरीत अमेरिकी शैल गैस समूहों ने अपने निवेशों को सऊदी अरब की बजाय दूसरे क्षेत्रों में लगाना शुरू कर दिया है, जबकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था अधर में आ गई है। वर्ष 2015 में इसका राजकोषीय घाटा जीडीपी का तकरीबन 16% रहा, जिसके इस वर्ष तकरीबन 13% रहने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।
- पिछले एक दशक में पहली बार इस वर्ष सऊदी अरब 10 बिलियन डॉलर का पाँच वर्षीय विदेशी ऋण लेने जा रहा है। इस वर्ष उसकी अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 1 प्रतिशत तक धीमी होने की सम्भावना है। ऐसे में इसके पास अब अधिक विकल्प मौजूद नहीं रहे, अतः अर्थव्यवस्था में वापस लौटने के लिये इसे अपने मूल व्यवसाय कच्चे तेल के बाज़ार में वापस लौटना होगा।
- कथित तौर पर ओपेक द्वारा ईरान को कुछ विशेष छूट प्रदान की गई है ताकि ईरान तेल उत्पादन के क्षत्र से तत्काल ही अपनी हिस्सेदारी को कम कर दे जिससे कि ओपेक देशों के द्वारा आरम्भ की गई यह मुहिम कामयाब हो सके।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

टू द पॉइंट

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

भारत की शरणार्थी नीति

क्यों है खबरों में?

- ब्राहमदाग बुगती बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर बुगती (जिसे 2006 में पाकिस्तानी सेना द्वारा मार दिया गया था) के पौत्र हैं। साथ ही वे बलोच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक हैं।
- वे 2006 में पाकिस्तान से अफगानिस्तान पलायन कर गए थे और 2010 में स्विट्ज़रलैंड गए जहाँ स्विस प्राधिकरण के पास उनका राजनैतिक शरण (आश्रय अथवा Asylum) का आवेदन लंबित है।
- वे अब भारत में राजनैतिक शरण के लिये आवेदन करना चाहते हैं जिससे उनके लिये यात्रा करने के लिये दस्तावेज़ पाने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान के मुद्दे के लिये समर्थन हासिल करना संभव हो सकेगा।
- यदि सरकार का निर्णय उनके पक्ष में आता है तो बुगती को एक दीर्घकालीन वीज़ा प्रदान किया जा सकता है जिसका हर वर्ष पुनर्नवीकरण करना होगा। बुगती के संबंध में समस्या इतनी जटिल हो गई है कि गृह मंत्रालय के अधिकारी इसकी प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये 1959 के अभिलेखों को खंगाल रहे हैं।

राजनैतिक शरणार्थी और शरणार्थी में अंतर

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR), राजनैतिक शरण मांगने वाले (आश्रय याचक) को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो एक शरणार्थी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग करता है लेकिन आवेदन के समय के निरपेक्ष उनकी शरणार्थी के रूप में स्थिति अभी निश्चित नहीं की गई है।
- कोई व्यक्ति इस आधार पर राजनैतिक शरण के लिये आवेदन कर सकता है कि यदि वह अपने मूल देश में लौटता/लौटती है तो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनैतिक धारणा या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण उसे अपने उत्पीड़न की आशंका है।

  निम्नलिखित के अंतर्गत शरणार्थी मान्यता प्राप्त व्यक्ति है:
  - शरणार्थी के दर्जे से संबंधित यूनाइटेड नेशंस 1951 सम्मेलन
  - 1967 प्रोटोकॉल (Relating to the status of Refugees)
  - अफ्रीका में शरणार्थी समस्याओं के विशेष पहलुओं का प्रबंधन करने के लिये 1969 में बनी अफ्रीकी एकता संस्था
  - यूएनएचसीआर के विधान के अनुसार मान्यता प्राप्त लोग
  - पूरक सुरक्षा अथवा अस्थायी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति
  - 2007 से शरणार्थी आबादी में वे लोग भी जोड़े गए हैं जो 'शरणार्थियों जैसी स्थिति' में रह रहे हैं।

क्या भारत में आश्रय याचकों और शरणार्थियों के लिये एकसमान कानून है?

- हालाँकि, भारत में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी है लेकिन यहाँ अभी तक आश्रय याचकों के लिये एकसमान कानून नहीं बनाया जा सका है। भारत ने 1951 के शरणार्थी दर्जे के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन समझौते पर या 'मेज़बान राज्य' द्वारा आवश्यक रूप से शरणार्थियों को अधिकार और सेवाएँ देने से संबंधित प्रोटोकॉल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- अधिकारियों द्वारा विभिन्न कानून, जैसे-पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशी कानून, 1946 इत्यादि को ध्यान में रखकर शरणार्थियों और आश्रय याचकों के प्रवेश के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।
- ये कानून शरणार्थियों को अन्य विदेशियों के समतुल्य मानते हैं और इस बात का विचार नहीं करते कि मानवीय आधार पर उन्हें विशेष दर्जा मिलना चाहिये। दिसम्बर 2015 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्रय विधेयक, 2015 पेश किया जो भारत के शरणार्थियों को संगठित और सुव्यवस्थित करने के लिये कानूनी ढाँचे की स्थापना करेगा; यह विधेयक अभी विचाराधीन है।

इस संधि को स्वीकृत करने के भारत के लिये क्या अर्थ होंगे?

- यह किसी भी शरणार्थी को उसकी इच्छा के बिना उसके देश वापस न भेजने के लिये कानून द्वारा बाध्य हो जाएगा। इसे 'अवापसी नियम' कहते हैं, जिसका अर्थ है–किसी को बलपूर्वक उसके देश वापस न भेजना।
- पर भारत वैसे भी इस नियम से बंधा हुआ है क्योंकि यह 1984 के यंत्रणा विरोधी संधि में सम्मिलित है, जिसका भारत भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को मिलने वाली राहत

- जुलाई 2016 में सरकार ने भारत में दीर्घकालीन वीज़ा पर रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यकों के द्वारा सामना की जा रहीं समस्याओं को कम करने के लिये कई सुविधाओं को स्वीकृति प्रदान की।
- उन्हें बैंक खाता खोलने, अपने व्यवसाय के लिये संपत्ति खरीदने, सेवा-रोज़गार हेतु उपयुक्त स्थान खरीदने, स्वरोज़गार करने, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

आगे का रास्ता

- इन कानूनी मसलों को सुलझाने के लिये सबसे व्यावहारिक तरीका, सभी शरणार्थी समुदायों के लिये एकसमान आश्रय कानून को अपनाना होगा।
- यह आश्रय के सम्बन्ध में भारत की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली को संहिताबद्ध करने में मदद करेगा और हर बार शरणार्थी सुरक्षा का प्रश्न उठने पर ऐतिहासिक नीतियों को फिर से देखने की आवश्यकता को खत्म करेगा।
- एक राष्ट्रीय शरणार्थी नियम, समानांतर प्रणालियों की ज़रूरत को भी कम करेगा और भविष्य में आश्रय प्रबंधन के लिये एक सुव्यवस्थित तंत्र की स्थापना भी करेगा। ■■■

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

मानचित्रों

जाँचिये कि क्या आप इन नक्शों में

मानचित्र-1 समाचारों में रहे भारत के चर्चित स्थल

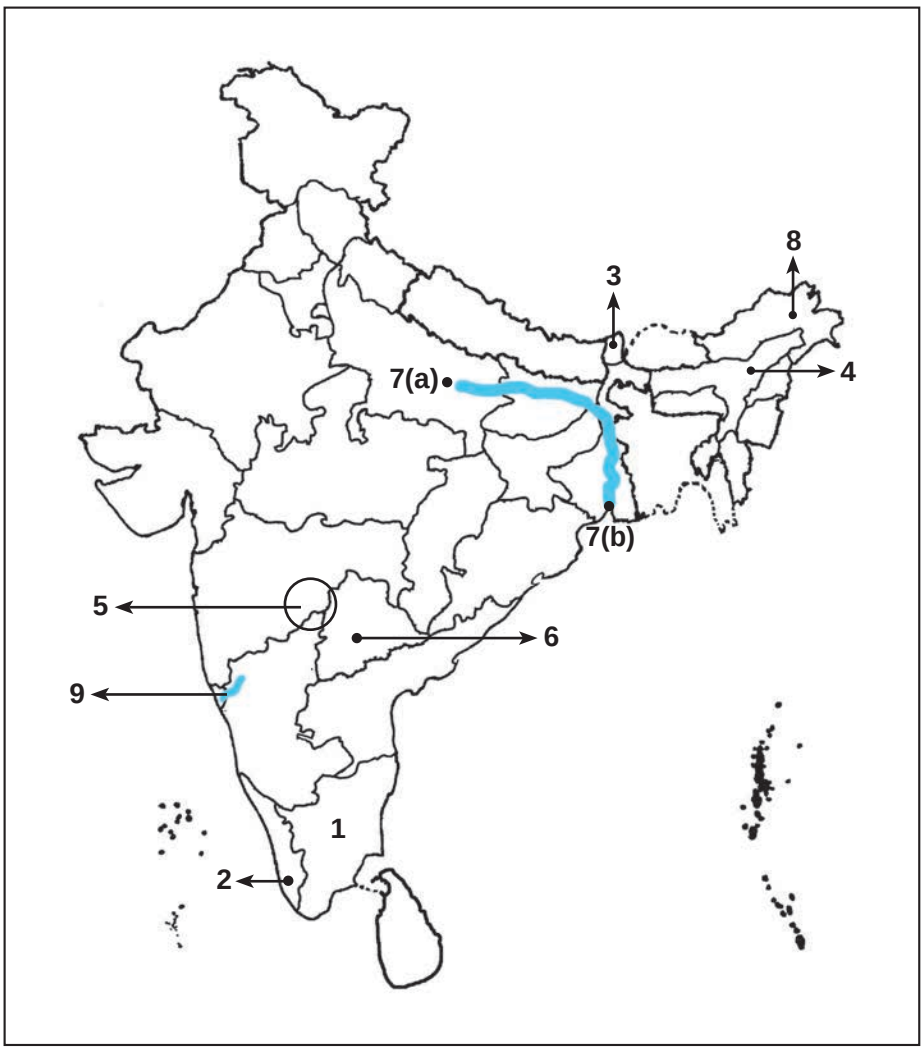

प्रश्न-

1. मानचित्र-1 में 1 के रूप में चिह्नित उस राज्य की पहचान करें, जहाँ हाल ही में रेलवे ने एक नवीनतम पहल की है।
2. 2 के रूप में चिह्नित केरल के उस शहर की पहचान करें, जो कि हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के द्वारा ठोस कचरे के प्रबंधन के आधार पर कराए गए सर्वेक्षण में सर्वाधिक स्वच्छता वाले शहर के रूप में उभरा है।
3. 3 के रूप में चिह्नित सिक्किम के उस स्थल की पहचान करें, जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किये गए तीन भारतीय स्थलों में से एक है। इसके अतिरिक्त सूची में शामिल होने वाले अन्य दो स्थलों के नाम क्या हैं जिन्हें मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है।
4. 4 के रूप में चिह्नित भारत के पहले द्वीप ज़िले की पहचान करें।
5. 5 के रूप में चिह्नित महाराष्ट्र के उस क्षेत्र की पहचान करें जो हाल ही के समाचारों में चर्चा में बना हुआ था। चर्चा में बने रहने के क्या कारण थे?
6. 6 के रूप में चिह्नित भारत के पहले ई-कोर्ट की शुरुआत करने वाले क्षेत्र की पहचान करें।
7. 7(a) और 7(b) के रूप में चिह्नित उन पारगमन बिन्दुओं की पहचान करें, जिनके बीच देश के पहले आंतरिक जल परिवहन द्वारा माल भेजने संबंधी कार्य का शुभारंभ किया गया।
8. 8 के रूप में चिह्नित अरुणाचल प्रदेश में स्थित उस क्षेत्र की पहचान करें, जहाँ हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिये भारत के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन किया गया।
9. 9 के रूप में चिह्नित कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद की वजह बनने वाली नदी की पहचान करें।

(इस मानचित्र का उत्तर पेज-259 पर देखें)

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र-2 समाचारों में रहे वैश्विक स्थल

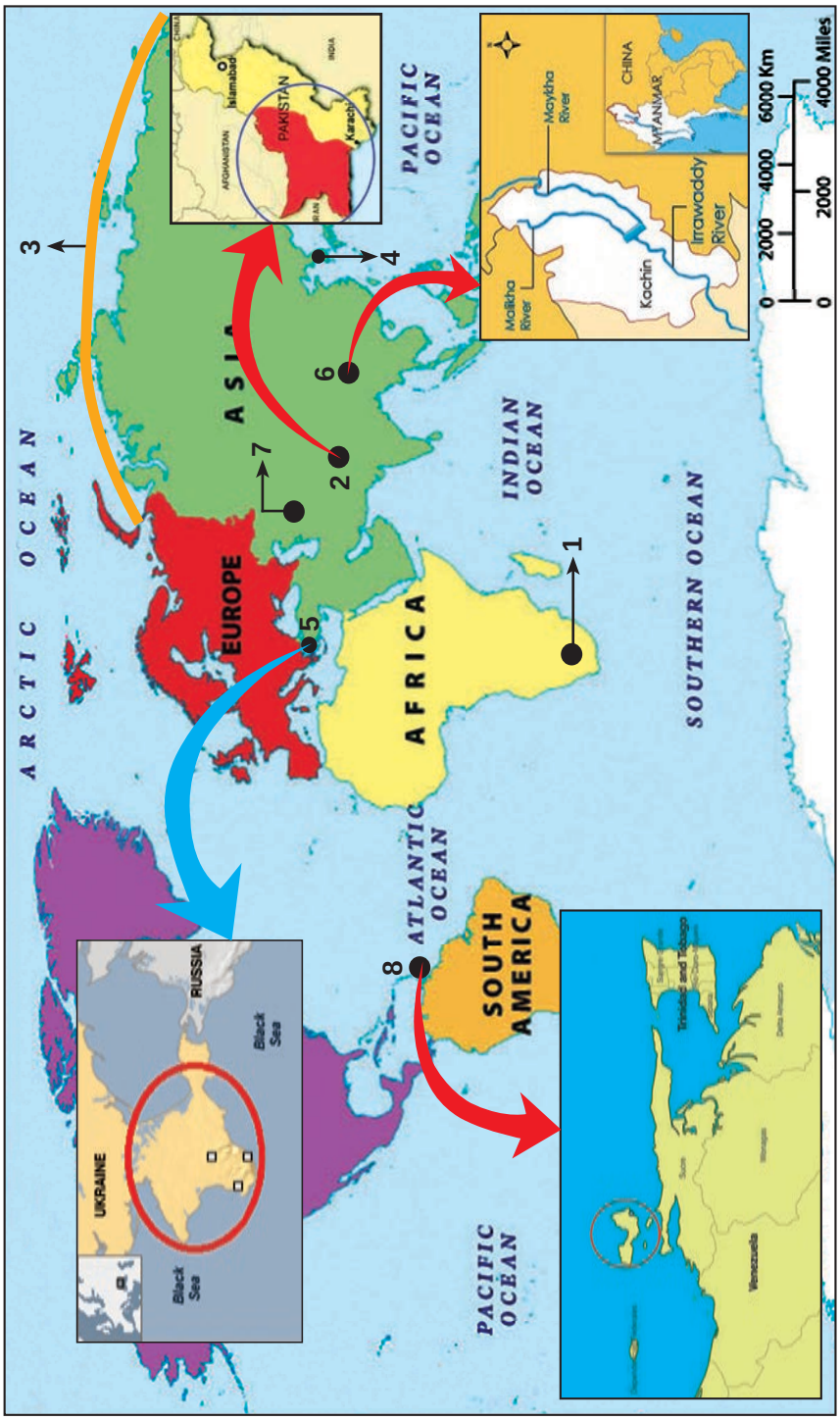

प्रश्न-

1. उस स्थल की पहचान करें, जहाँ गाड़ी की प्रथम श्रेणी से गांधीजी को बाहर फेंक दिया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उस स्थल का दौरा किया।
2. 2 के रूप में चिह्नित हाल ही में अलगाववादी आंदोलन के तौर पर चर्चा में रहने वाले क्षेत्र की पहचान करें।
3. 3 के रूप में चिह्नित नौ-परिवहन मार्ग की पहचान कर उसका महत्त्व रेखांकित करें।
4. 4 के रूप में चिह्नित हाल ही में हुए परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (एनएसजी) के वार्षिक पूर्ण सत्र की बैठक के आयोजन स्थल की पहचान करें।
5. 5 के रूप में चिह्नित दो यूरोपीय देशों के बीच विवादित प्रायद्वीप की पहचान करें।
6. 6 के रूप में चिह्नित हाल ही के समाचारों में चर्चा में रही नदी बांध परियोजना की पहचान करें।
7. 7 के रूप में चिह्नित वर्ष 2016 के शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल की पहचान करें।
8. 8 के रूप में चिह्नित वर्ष 2016 के गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल की पहचान करें।

(इस मानचित्र का उत्तर पेज-259 पर देखें)

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

प्रश्न: हाल के समय में देखा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उद्योगों को काफी कम ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, इस प्रवृत्ति के पीछे कौन-से प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं? इस समस्या से निपटने के लिये प्रमुख उपायों का उल्लेख कीजिये।

उत्तर: औद्योगिक विकास के लिये बैंक साख बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बैंक ऋण के अभाव में औद्योगिक निवेश प्रभावित होता है जिससे औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ रोज़गार की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिक विकास के लिये बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की भूमिका और बढ़ जाती है क्योंकि विकसित देशों की तरह यहाँ निजी क्षेत्र के पास पूंजी की उपलब्धता नहीं है।

बैंक ऋण की उपलब्धता में कमी के प्रमुख उत्तरदायी कारक

- भारत के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक गैर निष्पादित पूंजी की समस्या से जूझ रहे हैं जिसके कारण उनकी बैलेंस शीट दबावग्रस्त है और वे ऋण देने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।
- हाल के समय में जिस प्रकार से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी है उससे सरकार का ध्यान पुन: कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ा है। इससे बैंकों के ऊपर प्राथमिक क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ा है जिससे औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के लिये ऋण की उपलब्धता में कमी आई है।
- बाहरी क्षेत्र से मांग में कमी आ रही है क्योंकि चीन, यूरोपीय संघ आदि जैसी अर्थव्यवस्थाएँ मंदी का शिकार हैं। इसके कारण निवेशकों को निवेश करने में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है।
- बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने में कमी का एक प्रमुख कारण भारत में तेज़ी से बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण बैंकों के ऋण की काफी कम ज़रूरत होती है।
- स्टील एवं उर्वरक क्षेत्र काफी अधिक घाटे में चल रहे हैं, अत: इन क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों को कोई लाभ नहीं दिख रहा है।
- यद्यपि मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) के द्वारा रेपो रेट में कमी की गई है किंतु अधिकांश बैंक ब्याज की दर घटाने को तैयार नहीं दिखाई देते हैं।
- देश में अभी भी विभिन्न विनियामक एवं प्रक्रियात्मक संबंधी बाधाओं के कारण निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशकों के बीच भारी विभेद मौजूद है।

उपाय

- प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को तार्किक बनाया जाना चाहिये ताकि प्राथमिक क्षेत्र का ऋण अन्य क्षेत्रों को प्रभावित न करे।
- रिज़र्व बैंक द्वारा स्वयं बैंकों की निगरानी की जानी चाहिये ताकि बैंक समय से ब्याज दरों में कटौती को लागू कर सकें।
- दिवालिया (Bankruptcy Law) को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिये।
- ऋण वसूली प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी एवं सरल बनाया जाना चाहिये ताकि भविष्य में एनपीए (NPA) की समस्या से बचा जा सके।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि बैंकों की एनपीए की समस्या तथा अन्य आंतरिक एवं बाह्य कारकों के चलते उद्योग क्षेत्र को बैंकिंग ऋण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त उपायों के माध्यम से इस समस्या से निपटा जा सकता है।

प्रश्न: हाल ही में भारत में आयोजित ब्रिक्स एवं बिम्सटेक सम्मेलन पर टिप्पणी कीजिये। इन दोनों संगठनों का एक साथ भारत में आयोजन भारत के दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? इस आयोजन के नकारात्मक पक्षों को भी उद्घाटित कीजिये।

उत्तर: हाल ही में भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के आयोजन के माध्यम से भारत का विशेष प्रयास आतंकवाद के विरुद्ध रूस एवं चीन जैसे देशों को एकमत करना था ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद के पनाहगार के रूप में विश्व के समक्ष उजागर किया जा सके। चीन ने कुछ हिचक के साथ किंतु रूस ने पूरे समर्थन के साथ आतंकवाद से लड़ने के विरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त की।

ब्रिक्स सम्मेलन का महत्त्व

- इस सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठाया गया तथा सभी पाँचों देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक) से ऋण की प्रथम किस्त जारी करने पर निर्णय लिया गया। यह किस्त ब्रिक्स देशों में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित तकनीकी के विकास के लिये उपलब्ध कराई गई है।
- कृषि क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, खेल एवं रेटिंग एजेंसी की स्थापना के लिये ब्रिक्स देशों ने आपसी सहयोग पर बल दिया।
- इस दौरान भारत एवं रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई जिसमें व्यापार, निवेश एवं रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

ब्रिक्स एवं बिम्सटेक देशों के सम्मेलनों के एक साथ आयोजित होने का महत्त्व

- यह भारत की रणनीतिक एवं कूटनीतिक बढ़त को साबित करेगा क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित सार्क सम्मेलन को भारत के द्वारा बहिष्कृत किया गया था।
- सार्क संगठन पाकिस्तान की उपस्थिति के कारण काफी हद तक अप्रभावी रहा है, अत: भारत 'बिम्सटेक' जैसे संगठनों पर अधिक ज़ोर दे रहा है। ज्ञातव्य है कि 'बिम्सटेक' में पाकिस्तान नहीं है।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

पी.टी. एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिये संभावित प्रश्नोत्तरों का संकलन

भारतीय राजव्यवस्था

- यह व्यवस्था कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है किंतु इस समझौते की निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सकें। भारत का संविधान सामान्यत: इसी व्यवस्था को अपनाता है। यह व्यवस्था है–

  संघात्मक व्यवस्था

- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है–

  संसद को

- 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए तीन शब्द थे–

  समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखण्डता

- सामान्यत: संघ राज्य क्षेत्र केंद्रशासित होते हैं, किंतु जिन दो मामलों में इसका अपवाद दिखाई पड़ता है, वे हैं– *दिल्ली और पुदुच्चेरी*
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित वह समस्त भू-भाग जिस पर भारत की संप्रभुता का विस्तार है, कहलाता है– *भारत का राज्य क्षेत्र*
- पिछले कुछ समय में कई राज्यों में राजधानियों का नाम बदलने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। राजधानियों के नाम बदलने का कार्य है–

  विधानमंडलों का

- सन् 1975 में संविधान के 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस राज्य का 'सहयोगी राज्य' (Associate State) का दर्जा समाप्त करके इसे राज्यों की सूची में शामिल कर लिया गया। यह राज्य था– *सिक्किम*
- साधारणत: अवैध आप्रवासियों की नई पीढ़ियाँ इस स्थिति में होती हैं। कभी-कभी नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ों के अभाव में भी कोई व्यक्ति इस श्रेणी में आ सकता है। ये श्रेणी है– *राज्यविहीन व्यक्ति*
- संविधान लागू होने के बाद की स्थितियों के लिये नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है– *संसद को*
- नागरिकता के विषय पर भारतीय संविधान एकात्मक है, न कि संघात्मक। इसका अर्थ है कि भारत समर्थन करता है– *एकल नागरिकता का*
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3–7 के अंतर्गत वे पाँच तरीके, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है– *(i) जन्म से नागरिकता, (ii) वंश के आधार पर नागरिकता, (iii) पंजीकरण द्वारा नागरिकता, (iv) देशीयकरण द्वारा नागरिकता, (v) राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता*
- भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो साधारणत: अविभाजित भारत (1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार) से बाहर किसी देश में रह रहा हो, नागरिकता का अर्जन कर सकता है– *पंजीकरण द्वारा*
- विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत सरकार अलग से विशेष दर्जा देती है, जिसका संबंध उस व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से होता है। ऐसे तीन दर्जे प्रमुख हैं–

  (i) अनिवासी भारतीय (NRI), (ii) भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO), (iii) भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI)

- भारतीय नागरिकों की कॉमनवेल्थ नागरिकता की स्पष्ट व्याख्या की गई थी– *भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के पूरक खंड में*
- नागरिकता अधिनियम की धारा 6 में लंबे निवास के आधार पर नागरिकता का अर्जन करना कहलाता है– *देशीयकरण द्वारा नागरिकता*
- भारतीय मूल के व्यक्तियों को 2002 से यह कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड के धारकों को कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बिना वीज़ा भारत आ सकने की छूट मिली हुई है। यह है–

  भारतवंशी कार्ड (PIO Card)

- नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता की समाप्ति से संबंधित बताई गई तीनों स्थितियाँ हैं– *(i) नागरिकता का परित्याग, (ii) नागरिकता की समाप्ति, (iii) नागरिकता से वंचित किया जाना*
- नागरिकता अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर, 1992 को या उसके बाद हुआ हो तथा उसके माता-पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो, भारत की नागरिकता के लिये आवेदन कर सकता है– *वंश के आधार पर*
- विलय से पूर्व हैदराबाद में भारत सरकार की गुप्त सैन्य कार्यवाही को नाम दिया गया– *ऑपरेशन पोलो*
- भारत में विभिन्न रियासतों के विलय के समय ब्रिटेन के अलावा किन दो यूरोपीय देशों के उपनिवेश भारतीय भू-भाग पर थे–

  फ्राँस और पुर्तगाल

- भारत में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(2) के मुताबिक जहाज़ पर जन्मे बच्चे को उस देश का नागरिक माना जाएगा–

  जिस देश में जहाज़ पंजीकृत होगा

- विदेशों में रहने वाले जिन तीन श्रेणी के व्यक्तियों को भारत सरकार नागरिकता से अलग विशेष दर्जा देती है, उनमें से मताधिकार तथा संवैधानिक पदों या सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति की अर्हता प्राप्त है–

  अनिवासी भारतीयों को (Non Resident Indians)

- यह एक विशेष दर्जा है जो भारत सरकार ने 2005 से देना शुरू किया है। इससे संबंधित प्रावधान 'नागरिकता अधिनियम, 1955' में विशेष अनुच्छेद 7(क), (ख), (ग) तथा (घ) जोड़कर शामिल किये गए हैं। यह दर्जा है–

  भारत के समुद्रपारीय नागरिक (Overseas Citizens of India-OCI)

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

प्रेरणा खंड

आई.ए.एस. टॉपर निशांत जैन की कलम से...

कितना ज़रूरी है भाषा पर अधिकार...

"कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो
तू जिस जगह जगा सवेरे, उस जगह
से बढ़ के सो"

कवि भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियाँ किसी भी युवा के सर्वांगीण विकास के लिये प्रेरक हैं। आत्मविकास की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। हम प्रतिदिन अपने ज्ञान और अनुभव से कुछ नया सीखते हैं और उसे अपने व्यक्तित्व में जोड़ते जाते हैं। कुछ सुनना, कुछ पढ़ना, कुछ बोलना और कुछ लिखना ये चारों मिलकर हमारे व्यक्तित्व को हर रोज़ तराशते हैं और हम खुद में गुणात्मक सुधार कर प्रगति पथ पर बढ़ते जाते हैं।

भाषा पर अधिकार और अच्छी पकड़ होने का सिविल सेवा परीक्षा में कितना कारगर महत्त्व है, इसकी चर्चा करने के बाद हम प्रतियोगी परीक्षाओं में उपर्युक्त चार कौशलों में से विशेष महत्त्वपूर्ण लेखन कौशल पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यू.पी.एस.सी. में सफलता का आधार माने जाने वाले इस लेखन कौशल को कैसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है और किस प्रकार इसमें गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है।

भाषा के अन्य कौशलों की तरह ही लेखन कौशल पर भी पकड़ एक-दो दिनों में नहीं बनाई जा सकती। लेखन कौशल को बेहतर बनाने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य तत्त्व निरंतर अभ्यास है। हमें नहीं भूलना चाहिये कि-

"करत-करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निसान।"

लिहाज़ा अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियाँ दोनों को पहचानते हुए लेखन कौशल का अभ्यास शुरू करें। अभ्यर्थियों के सामने लेखन अभ्यास करने की दिशा में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इसे शुरू कैसे करें? तमाम अभ्यर्थी यही कहते हैं कि मुझे तो लिखना बिल्कुल नहीं आता.... यू.पी.एस.सी. के स्तर का लेखन कौशल तो बहुत दूर की कौड़ी है..... क्या मैं भी अच्छा लिखना सीख पाऊंगा..... मैं आई.ए.एस. टॉपर जैसा लेखन कौशल शायद ही कभी प्राप्त कर पाऊँ.....आदि-आदि।

विलियम फॉक्नर (William Faulkner) ने लिखा है, "Get it down, Take chances. It may be bad, but it's the only way you can do anything really good."

लेखन कौशल का अभ्यास शुरू करने की उलझन और उहापोह से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका उपर्युक्त उक्ति में ही छिपा है। यह बात अपने दिमाग से एकदम निकाल दें कि आप खराब लिखेंगे या फिर अच्छा लिखेंगे। बस आप लिखना शुरू कीजिये और फिर देखिये कि किस तेज़ी से आपके लेखन कौशल में सुधार आना शुरू होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आपका लेखन कौशल बेहतर हो या फिर बेहतर से कम हो, दोनों ही दशाओं में आपको लेखन कौशल का अभ्यास करना ही है। यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो भी अभ्यास से आपके लेखन का स्तर बेहतर ही होगा और अगर आप उतना अच्छा नहीं लिख पाते तो लेखन अभ्यास आपके लेखन कौशल में गुणात्मक और नाटकीय सुधार के लिये निश्चय ही अनिवार्य है।

आइये, उन तरीकों की बिंदुवार ढंग से चर्चा करते हैं जिनसे हम अपने लेखन कौशल में सुधार कर उसे उत्कृष्टता के स्तर तक ले जा सकते हैं-

- निरंतर अभ्यास की आदत बनाए रखें और इसे छूटने न दें। यह आदत आपके रूटीन का हिस्सा बन गई तो यह आपके प्रदर्शन और मार्कशीट में ज़बरदस्त सुधार ला सकती है।
- लेखन कौशल का अभ्यास करने के साथ-साथ लिखे गए उत्तरों/निबंधों/केस स्टडीज़ को किसी अच्छे अनुभवी मित्र या किसी मार्गदर्शक से जँचवाते रहें या फिर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़

परिचय

UPSC की वर्ष 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल करने वाले निशांत जैन, हिन्दी/भारतीय भाषाओं के माध्यम के टॉपर हैं। मुख्य परीक्षा में देश के तीसरे सर्वाधिक अंक (851 अंक) प्राप्त करने वाले निशांत ने निबंध के प्रश्नपत्र में 160 अंक और वैकल्पिक विषय- हिन्दी साहित्य में 313 अंक प्राप्त किये हैं, जो संभवत: सर्वाधिक अंक हैं।

मेरठ में पले-बढ़े, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले निशांत जैन, 2013 में अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे। नेट-जे.आर.एफ. उत्तीर्ण कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एम.फिल. उपाधि प्राप्त निशांत जैन लोक सभा सचिवालय के राजभाषा प्रभाग में दो साल सेवा कर चुके हैं।

कविताएँ लिखने और युवाओं से संवाद स्थापित करने में रुचि रखने वाले निशांत जैन भाषा-साहित्य-संस्कृति और वंचित वर्गों के कल्याण के क्षेत्र में गहरा रुझान रखते हैं। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) में राजस्थान कैडर मिला है।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

प्रेरणा खंड

आई.ए.एस. टॉपर डॉ. राजेन्द्र पैंसिया की डायरी...

आठवाँ पन्ना

"कदर किरदार की होती है,
वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है।"

इसी किरदार को जीवंत, भव्य और संवेदनशील बनाने के लिये अकादमी विविधतापूर्ण, चुनौतीपूर्ण और सर्वसमावेशी प्रशिक्षण करवाती है। इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि यदि इस प्रशिक्षण का आधा अनुसरण भी राज्यों की अकादमियाँ कर लें तो वे ज़मीनी स्तर के अधिक कार्यकुशल और क्षमतावान प्रशासक तैयार कर सकती हैं। हालाँकि अभी तक उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, किंतु सर्वोत्कृष्ट की संभावनाएँ कभी खत्म नहीं होतीं।

इसी क्रम में ही हमारी कम्प्यूटर क्लासेज़ भी आती हैं जो काफी गंभीर होती हैं। मेरा मानना है कि इस साइबर युग में हर किसी को तीन कार्य अवश्य आने चाहियें-टाइपिंग, कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान (MS Office, नेट सर्फिंग आदि) और अंग्रेज़ी भाषा का आधारभूत ज्ञान (क्योंकि कम्प्यूटर पर अधिकतम कार्य अंग्रेज़ी में ही होता है)। मैं ही नहीं, हममें से अधिकांश इस कम्प्यूटर नामक जिन से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक माह उपर्युक्त तीनों बातों पर ध्यान देने के बाद आप 'कम्प्यूटर मास्टर' बन सकते हैं। अकादमी में अधिकांश अधिकारियों को देखकर यही महसूस हुआ कि मैं बहुत पहले सफल हो सकता था, यदि मुझे इस सरल सी बात का पहले ज्ञान होता। सिविल सेवा की तैयारी में भी इसकी अत्यधिक उपयोगिता है और सिविल सेवा में सफल होने के बाद 'स्मार्ट ऑफिसर' बनाने में यह आधार का काम करता है। अत: हमें चाहिये कि इस पर पकड़ बनाएँ, जैसा कि मैंने स्वयं किया है।

इसके बाद बात आती है कक्षाओं की। मैंने पहले भी इस विषय में बात की थी। अब कुछ महत्त्वपूर्ण कक्षाओं की बात करना चाहूंगा। नचिकेत मोर सर की कक्षा बेहद शानदार रही जिसमें उन्होंने भारत के वित्तीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया। इकबाल धालीवाल जी की कक्षा तो लाजवाब थी। वे 1995 बैच के टॉपर हैं और एकमात्र IAS जिन्होंने यहाँ टॉपर रहने के बाद प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी में भी पब्लिक अफेयर्स में टॉप किया। आजकल वे J–PAL (The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी हैं। J-PAL गरीबी, लोक स्वास्थ्य, माइक्रोफाइनेंस और कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण, नीति-निर्माण में सहायता तथा क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देती है। यह मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में शोध केंद्र है। इकबाल सर ने यहाँ बेहतरीन सेवा देते हुए गरीबी पर पूरे विश्व में अच्छा कार्य किया। इस तरह एक IAS अधिकारी वसुधैव कुटुंबकम में भी अपना योगदान दे सकता है। इसलिये सिविल सेवा के अभ्यर्थियों और सिविल सेवकों, सभी को कुछ रिपोर्ट्स अवश्य देखनी चाहियें, जिनमें से एक है- J–PAL.

इसके बाद प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव पी.के. मिश्रा सर, माननीय वित्त राज्य मंत्री, माननीय रक्षा राज्य मंत्री इत्यादि की कक्षाएँ हुईं जो बेजोड़ थीं। हम फ्राँसिस फुकुयामा सर की कक्षा से वंचित रह गए जो हमारे प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद आए।

इसके अलावा, हमारी अकादमी में विभिन्न राज्यों के दिवस भी मनाए जाते हैं जिनसे राज्यों के पकवान खाने और उनकी संस्कृति को समीप से देखने व जीने का अवसर मिलता है, जैसे- राजस्थान दिवस के दिन दाल-बाटी-चूरमा तो तेलंगाना दिवस पर दक्षिण भारतीय व्यंजन बनते हैं। इसमें हमारे प्रशिक्षक भी आते हैं। इस तरह इससे न केवल हमें एक्सपोज़र मिलता है, अपितु

परिचय

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया का जन्म श्रीगंगानगर ज़िले के श्रीकरणपुर कस्बे में हुआ। इन्होंने बी.कॉम., बी.एड., बी.ए. (एडीशनल, अंग्रेज़ी), एम.ए. (अंग्रेज़ी), एम.ए. (भूगोल), नेट/जे. आर.एफ. (भूगोल), गांधी दर्शन में डिप्लोमा और पारिस्थितिकी में पी.एच.डी. की है। डॉ. राजेन्द्र का अनुभव-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इन्होंने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में टॉप किया तथा 6 वर्षों तक अध्यापक रहे। इसके उपरान्त आर.ए.एस. की परीक्षा में सफल होकर बी.डी.ओ. बने। इस पद पर अभी 4 महीने ही हुए थे कि अगली आर.ए.एस. परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल करके एस.डी.एम. बन गए और चार वर्षों तक इसी पद पर प्रभावशाली तरीके से काम करते रहे। 2014-15 की सिविल सेवा परीक्षा में इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के लिये हुआ। इन्हें सेवा के लिये उत्तर प्रदेश कैडर दिया गया है।

डॉ. राजेन्द्र की प्रिय रुचियों में बैडमिंटन खेलना, साहित्य पढ़ना, लेखन-कार्य करना, दूसरों से बातें करना, चर्चाओं तथा वाद-विवाद में भाग लेना तथा बच्चों का मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन करने की इस रुचि के कारण ही उन्होंने यह शृंखला लिखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार की है।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

प्रेरणा खंड

प्रिय अभ्यर्थियों,

'प्रेरणा खंड' की इस कड़ी में श्री प्रेमसुख डेलू भी हमारे साथ हैं। अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रेमसुख की आई.पी.एस. बनने तक की यात्रा स्वयं में एक प्रेरणादायी कहानी है। गरीब व ग्रामीण पृष्ठभूमि के कई अभ्यर्थियों के सिविल सेवक बनने के सपने सिर्फ इसलिये टूट जाते हैं कि वे हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कुछ उम्मीदवार हिम्मत करके आगे बढ़ते भी हैं तो कुछ दूरी तय करने के बाद असफलता को अपनी नियति मान बैठते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को संदेश देती यह प्रेरणा प्रेमसुख के संघर्षमय जीवन पर आधारित है। हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी को दिशा देने में यह सहायक सिद्ध होगी।

आई.पी.एस. पद पर चयनित प्रेमसुख डेलू की सफलता यात्रा...

देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद मुझे इस परीक्षा में शामिल होने वाले हज़ारों विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष (सोशल साइट्स) रूप से मुखातिब होने का मौका मिला। साथ ही, कुछ सहज एवं स्वाभाविक तथा कुछ अत्यंत गंभीर प्रश्न, जैसे *"क्या गरीब व ग्रामीण विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर सकता है? क्या हिन्दी माध्यम का प्रतिभागी इस परीक्षा में सफल हो सकता है?"* आदि। ये सवाल कई बार बड़े अजीब लगे पर आँकड़ों पर नज़र दौड़ाई तो कुछ सच्चाई नज़र आई। मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि हिन्दी माध्यम का विद्यार्थी इतना चिंतित क्यों है? मैं चाहूंगा कि आपकी यह चिंता दूर हो, इसलिये आपके दिमाग में तेज़ी से भाग रहे ऐसे हज़ारों प्रश्नों का जवाब मैं अपने अनुभवों एवं व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों से देने का प्रयास करूंगा।

सबसे पहली बात यह कि क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो मेरा उत्तर होगा 'हाँ'। इसका उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पिताजी 4 भाई थे और हमारे घर (संयुक्त परिवार) में कुल 25 सदस्य थे। एक छोटा-सा घर था। घर में कुल मिलाकर 15 बच्चे थे। हाथ में मिट्टी या लौह की स्लेट लेकर सभी गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। वापस घर आने के बाद हम लोग भी वही सामान्य काम करते थे जो पश्चिमी राजस्थान में आम विद्यार्थी करते हैं, जैसे खेत जाना, पशु चराने जाना, छुट्टी के दिन कभी ग्राउंड नट की चुगाई करने जाना तो कभी गलियों में आइसक्रीम बेचकर पॉकेटमनी प्राप्त करना आदि। बाद में जब संयुक्त परिवार अलग हुआ तो ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। पिताजी-माताजी अनपढ़ और हम धूर रेगिस्तान के निवासी जहाँ शायद ही कभी बारिश होती है। पूरी शिक्षा जैसे-तैसे सरकारी स्कूल से पूरी की।

"जहाँ तक माध्यम की बात है तो इसे लेकर कभी चिंता में न रहें। अपना माध्यम हिन्दी है तो है, इस बात को अपने मन में दृढ़ता से स्वीकार कर लें तथा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो अतिरिक्त प्रयास करने की। अधिक-से-अधिक मॉक टेस्ट दें, प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ें, फिर टू-द-प्वाइंट उत्तर लिखें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करें, कोशिश करें कि किसी भी पेपर में एक भी प्रश्न न छूटे, कम-से-कम पुस्तकें पढ़ें, सिर्फ प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें, केवल रंगीन कलेवर देखकर पुस्तकें न खरीदें और पुस्तकों को बार-बार पढ़ें।"

यह कहानी केवल मेरी ही नहीं शायद गाँव से आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की है, बस थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ। अपने इस अनुभव को आपके साथ साझा करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम इस पृष्ठभूमि का हर जगह रोना रोते हैं। दोस्तों, हमें हमारे हिन्दी माध्यम एवं इस पृष्ठभूमि पर गर्व होना चाहिये क्योंकि यह

परिचय

प्रेमसुख डेलू राजस्थान के बीकानेर ज़िले के रहने वाले हैं। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले प्रेमसुख ने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अदम्य उत्साह के साथ लगातार सफलताएँ प्राप्त कीं। पटवारी की नौकरी से शुरू करते हुए प्रेमसुख ने ग्राम सेवक, सहायक कारापाल, वरिष्ठ अध्यापक, सब इंसपेक्टर और स्कूल व्याख्याता से होते हुए वर्ष 2012 में R.A.S. परीक्षा में 108वीं रैंक हासिल की। वर्ष 2015 की सिविल सेवा परीक्षा में इनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S.) के लिये हुआ। सेवा के लिये इन्हें उत्तर प्रदेश कैडर प्राप्त हुआ है।

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

टॉपर से बातचीत...

अवध किशोर पवार

UPSC-2015 में उच्च स्थान पर चयनित

टॉपर से बातचीत की इस कड़ी में हमारे साथ हैं– सिविल सेवा परीक्षा-2015 में उच्च स्थान पर चयनित श्री अवध किशोर पवार। अवध जी को उनकी शानदार सफलता के लिये ढेरों बधाइयाँ। 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की टीम से बातचीत के दौरान अवध जी ने इस परीक्षा में सफलता को लेकर अपनी रणनीति जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और इस क्षेत्र में प्रयासरत अभ्यर्थियों को सफलता के महत्त्वपूर्ण सूत्र दिये। यहाँ हम उनसे हुई बातचीत को प्रस्तुत कर रहे हैं।

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे: सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

अवध किशोर पवार: *शुक्रिया। काफी समय के बाद सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में नाम आना सुखद अनुभव रहा।*

दृष्टि: क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

अवध: *यह परीक्षा मेरे लिये ज़रूरी पड़ाव है जिसे एक माध्यम बनाकर स्वयं का और समाज का जीवन बेहतर किया जा सकता है। जीवन में कुछ विशेष फुटप्रिंट छोड़कर जाने के लिये सिविल सेवा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।*

दृष्टि: सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था?

अवध: *प्रति वर्ष लाखों अभ्यर्थी इस सेवा में शामिल होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ एक सुरक्षित कॅरियर विकल्प, सोशल स्टेटस और बेहतर सुविधाएँ हैं। साथ ही, अथॉरिटी और संसाधनों की उपलब्धता को आम जीवन को प्रभावित करने का माध्यम माना जाता है। मेरे लिये भी यही सभी कारण सिविल सेवा के प्रति आकर्षण के लिये उत्तरदायी हैं।*

दृष्टि: अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे?

अवध: *इस परीक्षा की तैयारी इतने समय में संभव है, हालाँकि कई कारक इसे प्रभावित करते हैं। मैंने स्वयं प्रथम प्रयास से ही लगातार इंटरव्यू दिये हैं, परंतु यहाँ कॉम्पटीशन की तीव्रता इतनी है कि एक गलती महँगी साबित हो सकती है। मैं स्वयं अपने पिछले दो प्रयासों में 9 अंक (2014) एवं 16 अंक (2013) से अंतिम चयन सूची में नहीं आ सका था। इसलिये सही दिशा में सतत् प्रयास से सफलता मिल सकती है। मैं अपनी मुख्य परीक्षा से काफी संतुष्ट था और आशावान होकर परिणाम का इंतज़ार कर रहा था।*

दृष्टि: यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन-से सूत्र रहे?

अवध: *मैंने लगातार अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास किया। खुले मस्तिष्क से उनको दूर करने की कोशिश की। अच्छे मित्र, सीनियर, सफल छात्रों तथा अध्यापकों को साथ बनाए रखा। प्रामाणिक अध्ययन सामग्री के साथ, कम पुस्तकों का अधिक बार रिवीज़न फायदेमंद रहा। साथ ही, प्री-मेंस दोनों में ही टेस्ट सीरीज़ पर काफी ध्यान दिया। सकारात्मक माहौल बनाकर, मस्तिष्क को शांत-प्रसन्न रखने का प्रयास किया। अंततः धैर्य व सतत् प्रयास सफलता की ओर ले गए।*

दृष्टि: आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे?

अवध: *सिविल सेवा परीक्षा में मुझे कई अच्छे लोगों का साथ मिला। मेरे माता-पिता खेतों में कठिन परिश्रम करके भी लगातार मुझे प्रोत्साहन देते रहे। साथ ही, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों से भी इस परीक्षा में काफी मदद मिली। मेरे दोस्त- नीरज कुमार (UPPCS), चंद्रकांता राठौर (IFS), दुष्यंत मौर्य (SDM), देवीलाल (IAS), अर्पित जैन (IPS), पुनीत चौधरी, आलोक सर (BDO), मयंक यादव, मानवेन्द्र, डॉ. मुकेश काजरा (DANICS) आदि का अभूतपूर्व सहयोग रहा।*

साथ ही, तीन बार इंटरव्यू में असफल होने पर भी हौसला बनाए रखने और ग्रुप-स्टडी में मेरे दोस्तों का सहयोग अविस्मरणीय है।

दृष्टि: आपका वैकल्पिक विषय क्या था?

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com

टॉपर से बातचीत...

कृष्ण कुमार पाण्डेय

MPPSC में उप-पुलिस अधीक्षक (Dy. S.P.) के लिये चयनित

टॉपर से बातचीत की कड़ी में इस बार हमारे साथ हैं- 2013 की एमपीपीएससी परीक्षा में उप-पुलिस अधीक्षक के लिये चयनित कृष्ण कुमार पाण्डेय। स्वभाव से शांत, सरल और सौम्य कृष्ण ने अपने पहले ही प्रयास में एमपीपीएससी में सफलता हासिल की। हालाँकि, कृष्ण का लक्ष्य आई.ए.एस. बनना है। हमारे साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सफलता और वर्तमान में जारी यूपीएससी की तैयारी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। यहाँ हम उनसे हुई चर्चा को ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं।

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे: एमपीपीएससी परीक्षा में उप-पुलिस अधीक्षक पद पर चयनित होने पर आपको 'हमारी' ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

कृष्ण: *धन्यवाद, अच्छा लग रहा है।*

दृष्टि: क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

कृष्ण: *इस परीक्षा में सफल होना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं, परंतु यह एक पड़ाव ज़रूर था। अभी मैं यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ, वो भी एक पड़ाव होगा।*

दृष्टि: अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे?

कृष्ण: *नहीं, अगर रणनीति सही हो और आप परीक्षा विशेष की ज़रूरतें समझ रहे हों तो तैयारी के ऐसे स्तर पर पहुँचा जा सकता है जो संतोषजनक हो। मैं अपनी तैयारी के दौरान ज़्यादातर मामलों में संतुष्ट था, निश्चित तौर पर कई ऐसे खंड थे, जिनमें लगता था कि अभी और तैयारी की आवश्यकता है, परंतु सफल होने की आशा आगे की तरफ प्रेरित करती रहती है।*

दृष्टि: यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन-से सूत्र रहे?

कृष्ण: *पिछले प्रश्नपत्रों और पाठ्यक्रम (Syllabus) को तकरीबन रोज़ देखने की आदत। इससे प्रश्नों की गहराई और विस्तार का सटीक ज्ञान होता है और हम पाठ्यक्रम के बड़े सागर में से वरीयता के अनुसार ज़रूरत की चीज़ें पढ़ने के बारे में सटीक रणनीति बना पाते हैं।*

दृष्टि: आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे?

कृष्ण: *विकास सर और संपूर्ण दृष्टि टीम, अंबुज सर, नीलेश सर, मेरा परिवार, अमृत जी, प्रगति दीदी और मेरे दोस्त।*

दृष्टि: आपके वैकल्पिक विषय क्या थे? क्या आपने इनकी पढ़ाई स्नातक या आगे के स्तर पर की थी? यदि नहीं, तो इनके चयन का आधार क्या था?

कृष्ण: *हिन्दी साहित्य और समाजशास्त्र मेरे वैकल्पिक विषय थे। मैंने इन दोनों विषयों की पढ़ाई स्नातक स्तर पर नहीं की थी। हालाँकि परीक्षा देने के बाद मैंने हिन्दी साहित्य से एम.ए. किया। हिन्दी साहित्य का चुनाव मैंने रुचि की वजह से किया था और समाजशास्त्र का ज़रूरत की वजह से (परीक्षा में स्कोरिंग की वजह से)।*

दृष्टि: कई लोग कहते हैं कि कुछ वैकल्पिक विषय दूसरे विषयों की तुलना में छोटे, आसान व अधिक अंकदायी होते हैं और इसीलिये वे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। आपकी राय में क्या यह बात ठीक है? क्या आपने वैकल्पिक विषयों के चयन में उनकी लोकप्रियता को भी आधार बनाया था?

कृष्ण: *नहीं, विषय का चयन मुख्यत: रुचि के हिसाब से होना चाहिये। अगर कई विषयों में रुचि है तो फिर परीक्षा-प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुनाव करना चाहिये, जैसे- सामान्य अध्ययन में उस विषय का योगदान या हिन्दी माध्यम में पाठ्य-सामग्री की उपलब्धता।*

दृष्टि: प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए इसकी तैयारी के लिये आपने क्या रणनीति अपनाई- कुछ विशेष खंडों पर अधिक बल दिया या सभी पर समान बल? आपकी राय में क्या कुछ खंडों को गौण मानकर छोड़ा जा सकता है?

Daily Current Affairs | Govt. Jobs | SSC | Bank | Railway | IAS-PCS | GK | eBooks
तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी मे SarkariHelp.com